गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 241
दि. 01.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुभकामनाएं दीं

(जीएनएस)।

अयोध्या में राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश और विश्वभर के भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

श्री मोदी ने राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा वर्षगांठ को भारत की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का दिव्य उत्सव बताया। उन्होंने भारत और विदेश के असंख्य भक्तों की ओर से भगवान श्री राम के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन किया और सभी देशवासियों को अपनी असीम शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने सदियों पुराने संकल्प के ऐतिहासिक रूप से पूरा होने का स्मरण करते हुए कहा कि भगवान श्री राम की कृपा और आशीर्वाद से लाखों भक्तों की पांच शताब्दियों की पवित्र मनोकामना पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि राम लला फिर से अपने भव्य निवास में विराजमान हैं और यह वर्ष अयोध्या में धर्म ध्वज और राम लला की प्रतिष्ठा द्वादशी के गौरव का साक्षी है। प्रधानमंत्री ने पिछले माह इस धर्म ध्वज की पुण्य स्थापना का अवसर मिलने को अपना परम सौभाग्य बताया।

श्री मोदी ने कामना की कि मयार्दा पुरूषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रेरणा से प्रत्येक नागरिक के हृदय में सेवा, समर्पण और करुणा की भावना गहरी हो। उन्होंने कहा कि ये मूल्य समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सशक्त आधार हैं।

सोशल मीडिया एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट में, श्री मोदी ने लिखाः

"अयोध्या जी की पावन धरा पर आज रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्षगांठ हमारी आस्था और संस्कारों का एक दिव्य उत्सव है। इस पावन-पुनीत अवसर पर देश-विदेश के सभी रामभक्तों की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन और वंदन! समस्त देशवासियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं।

"भगवान श्री राम की असीम कृपा और आशीर्वाद से असंख्य रामभक्तों का पांच सदियों का संकल्प साकार हुआ है। आज रामलला अपने भव्य धाम में पुनः विराजित हैं और इस वर्ष अयोध्या की धर्म ध्वजा, रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी की साक्षी बन रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले महीने मुझे इस ध्वजा की पुण्य स्थापना का सुअवसर मिला।"

"मेरी कामना है कि मयार्दा पुरुषोत्तम की प्रेरणा हर देशवासी के हृदय में सेवा, समर्पण और करुणा की भावना को और प्रगाढ़ करे, जो समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार भी बने।

वेस्ट वॉटर नहीं बनेगा बोझ! भविष्य की 'प्यास' बुझाने के लिए सीएम योगी का मेगा प्लान तैयार

(जीएनएस)।

योगी सरकार ने साल 2030 तक 50 फीसदी और 2035 तक 100 फीसदी वेस्ट वॉटर का सुरक्षित पुनः उपयोग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है. इससे कृषि से लेकर इंडस्ट्री तक में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा.

यूपी की योगी सरकार जल सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है. योगी सरकार ने साल 2030 तक 50 फीसदी और 2035 तक 100 फीसदी वेस्ट वॉटर का सुरक्षित पुनः उपयोग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है. इससे कृषि से लेकर इंडस्ट्री तक में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके लिए व्यापक नीति, चरणबद्ध कार्ययोजना और मजबूत क्रियान्वयन तंत्र तैयार किया गया है. यह पहल न सिर्फ जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ जल प्रबंधन की मजबूत नींव भी रखेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत अब वेस्ट वॉटर को बोझ नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधन के रूप में विकसित किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही नीति के तहत उपचारित जल का उपयोग नगर निकायों के कार्यों, इंडस्ट्री, कृषि एवं गैर-पेय घरेलू उपयोग में किया जाएगा.

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वग्राही विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

34 जिलों की जिला पंचायतों के अध्यक्षों को 1 करोड़ रुपए का वार्षिक विवेकाधीन अनुदान स्थानीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवंटित किया जाएगा

गांधीनगर, 31 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वग्राही तथा सर्वसमावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण जन हितकारी निर्णय किए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से राज्य की सभी 34 जिला पंचायतों के अध्यक्षों को 1 करोड़ रुपए का विवेकाधीन अनुदान सम्बद्ध जिलों के स्थानीय महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए आवंटित करने के दिशानिर्देश दिए हैं।

राज्य में विधायकों को विकेन्द्रित जिला योजना कार्यक्रम अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान आवंटित करने की परंपरा है।

मुख्यमंत्री के समक्ष जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपने जिले में ग्रामीण विकास कार्यों को वेग मिले और स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जा सके; इस आशय से जिला पंचायत अध्यक्षों को भी विवेकाधीन अनुदान आवंटित करने की प्रस्तुतियाँ-मांग की थीं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन प्रस्तुतियों पर सकारात्मक तथा त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए यह एक करोड़ रुपए का विवेकाधीन अनुदान जिला पंचायत अध्यक्ष को आवंटित करने के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को दिया है।

राष्ट्रपति ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नव वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है, "नए साल के शुभ अवसर पर, मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं।" नव वर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। यह आत्मचिंतन और नए संकल्पों का भी अवसर है। इस अवसर पर, आइए हम राष्ट्र के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। "वर्ष 2026 हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाए और एक मजबूत तथा अधिक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा का संचार करे।"

डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी 31 दिसंबर 2025 को 'लैंड स्टैक' का शुभारंभ करेंगे और 'राजस्व शर्तों की शब्दावली' जारी करेंगे

भूमि प्रशासन में पारदर्शिता लाने और नागरिकों के लिए "जीवन को सुगम बनाने" की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

(जीएनएस)।

डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत भूमि प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने 31 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और तमिलनाडु के चिन्हित स्थलों पर 'लैंड स्टैक' (भूमि-प्रणाली) का शुभारंभ किया और साथ ही 'राजस्व शर्तों की शब्दावली' (जीओआरटी) भी जारी की है।

ये पहल आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित भूमि शासन की दिशा में एक बदलाव का प्रतीक हैं। यह पहल भारत की ऐतिहासिक भूमि अभिलेख प्रणालियों को समकालीन डिजिटल शासन की मांगों के अनुरूप बनाती हैं।

सिंगापुर, ब्रिटेन और फिनलैंड जैसे देशों में प्रचलित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम तौर-तरीकों से प्रेरणा लेते हुए, लैंड स्टैक को एक एकीकृत, जीआईएस-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया है।

वर्तमान में, नागरिकों को अक्सर विभिन्न विभागों से आधी-अधूरी जानकारी प्राप्त होती है। लैंड स्टैक नागरिकों और सरकारी एजेंसियों दोनों के लिए भूमि और संपत्ति सम्बंधी जानकारी तक एकल पहुंच प्रदान करके इस समस्या का समाधान करता है।

लैंड स्टैक के लाभः लैंड स्टैक पोर्टल भूमि सम्बंधी जानकारी तक एकीकृत पहुंच के माध्यम से नागरिकों को सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इससे नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और विश्वास में वृद्धि होती है। इससे अनधिकृत या नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों की अनजाने में खरीद का जोखिम कम हो जाता है। यह अंतर-विभागीय समन्वय को बेहतर बनाता है और डेटा-आधारित शासन को बढ़ावा देता है। यह भूमि प्रशासन में एक महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस सुधार का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत का भूमि प्रशासन टोडरमल के राजस्व सुधारों से लेकर ब्रिटिश बंदोबस्ती प्रणालियों (रैयतवारी, महलवारी) तक विविध ऐतिहासिक प्रभावों से आकारित है। इसके परिणामस्वरूप, खसरा, दाग या पुला जैसे शब्द समान अवधारणाओं को संदर्भित कर सकते हैं, जबकि एक ही शब्द के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए, कृषि विभाग ने पुणे के यशदा स्थित भूमि प्रशासन और प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई-एलएएम) के सहयोग से राजस्व शर्तों की शब्दावली तैयार की है।

जीओआरटी की मुख्य विशेषताएंः

यह स्थानीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और रोमन लिपियों में भूमि से सम्बंधित विभिन्न राजस्व शब्दों के अर्थ प्रदान करता है ।

इसका उद्देश्य बिना राज्य-विशिष्ट शब्दावली को प्रतिस्थापित किए शब्दावली में सामंजस्य स्थापित करना है ताकि भूमि सम्बंधी आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय और अंतर-संचालनीय बनाया जा सके।

यह राजस्व अधिकारियों, नीति निमार्ताओं, न्यायिक अधिकारियों और नागरिकों के लिए एक आधिकारिक संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

इन पहलों की शुरूआत देश के विविध भूमि प्रशासन में सामंजस्य लाने के लिए एक सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने सिस्टम इंजीनियरिंग फैसलिटी के उद्घाटन के साथ अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया

नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्टार्ट-अप तथा एमएसएमई के लिए समर्थन को बढ़ावा मिला

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने 31 दिसंबर 2025 को सिस्टम इंजीनियरिंग फैसिलिटी (एसईएफ) के उद्घाटन के साथ अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की सचिव एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेवानिवृत्त कमोडोर अमित रस्तोगी ने सात दशकों में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की यात्रा और गहन प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को सक्षम बनाने, स्टार्ट-अप और एमएसएमई का समर्थन करने तथा अनुसंधान परिणामों और बाजार में तैनाती के बीच की खाई को पाटने वाले मजबूत संस्थागत तंत्रों के निर्माण पर इसके नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की रणनीतिक पहलों, जिनमें विकसित भारत@2047, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत शामिल हैं, पर बल दिया और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के निर्माण के प्रति राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की प्रतिबद्धता को दोहराया।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के संबोधन के बाद, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन सिस्टम्स इंजीनियरिंग (आईएनसीओएसई) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान हुआ। यह समझौता ज्ञापन सहयोगात्मक नवाचार और क्षमता निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य सिस्टम इंजीनियरिंग प्रणालियों को सुदृढ़ करना है।

इस अवसर का एक प्रमुख आकर्षण सिस्टम इंजीनियरिंग फैसलिटी (एसईएफ) का उद्घाटन था, जो महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (पीसीसीओई) के साथ रणनीतिक सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय पहल है। सिस्टम इंजीनियरिंग फैसलिटी का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. एन. कलाइसेल्वी, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सेवानिवृत्त) कमोडोर अमित रस्तोगी और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के

तीन दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

श्री शिवराज सिंह, एक जनवरी नए वर्ष पर शिरडी के पास ग्राम लोणी बुदरुक में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीण जनों, श्रमिक और मजदूर भाई बहनों से संवाद करेंगे

अहिल्या नगर और नासिक में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और नासिक जिलों के दौरे पर रहेंगे। उनका यह दौरा किसानों, ग्रामीण विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं के लिए नए अवसरों को समर्पित रहेगा, जिसमें वे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार की किसान और ग्रामीण हितैषी नीतियों की जानकारी देंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 31 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अहिल्यानगर (अहमदनगर) में कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे यहां बाभलेश्वर में कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करेंगे और कृषक समूहों से मुलाकात करेंगे, वहीं किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श तथा क्षेत्र की विशेष चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा भी उनके कार्यक्रमों में शामिल रहेगी।

श्री शिवराज सिंह किसानों के साथ सीधे संवाद कर फसल, सिंचाई, जल-संरक्षण, फसल बीमा, बाजार तक बेहतर पहुंच और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। अहिल्यानगर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक के उपयोग, फसल विविधिकरण, मूल्य संवर्धन और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से संगठित कृषि को बढ़ावा देने पर अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान, 1 जनवरी 2026 को पौधारोपण करने के साथ प्रातः 10 से 11 बजे तक नव वर्ष के अवसर पर अपने दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों को वर्चुअल सम्बोधन कर संकल्प दिलाएंगे। दोपहर दो बजे से वे ग्राम लोणी बुदरुक में ग्राम सभा कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे, जहां ग्रामीणजन, मजदूर श्रमिक भाई बहनों से संवाद भी करेंगे।

नासिक में 2 जनवरी को प्रमुख कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (उटडव) में आयोजित होगा, जहाँ श्री चौहान का दोपहर 12.15 बजे से विस्तृत सत्र निर्धारित है। कार्यक्रम के अनुसार, कुलपति एवं वरिष्ठ अधिकारियों से सौजन्य भेंट के बाद सभागार में औपचारिक उद्घाटन में केंद्रीय कृषि मंत्री शामिल होंगे। यहां उनका उद्बोधन होगा, साथ ही प्रश्नोत्तर और इंटरैक्टिव सत्र के माध्यम से विद्यार्थियों, शोधार्थियों से वे संवाद करेंगे।

सम्पादकीय

नव वर्ष 2026 में प्रगति पथ पर भारत

स्वागत है 2026! वर्ष 2025 का समापन और 2026 का शुभारंभ हो गया है। व्यक्तिगत रूप से वुछ लोगों के लिए वर्ष 2025 अच्छा रहा होगा और वुछ लोगों के लिए अत्यन्त दुखद। वुछ लोगों के लिए गत वर्ष मिश्रित रहा होगा किन्तु यदि देश के स्तर पर बात की जाए तो वर्ष 2025 वुछ मामलों में तो अच्छा रहा जैसे आर्थिक विशेष रूप से विकास दर को लेकर भारत की आर्थिक मोच्रे पर प्रागति को देखकर कई देशों ने अपनी आर्थिक रणनीति में बदलाव कर लिया। ब्रिटेन और प्रांस को तो पहले ही पछाड़ दिया था भारत ने लेकिन 2025 में भारत जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। दुनिया की रेटिग एजेंसी भारत की जीडीपी को 7 प्रातिशत से ज्यादा नहीं आंक रही थी किन्तु वास्तव में यह आंकड़ा 8.2 प्रातिशत का निकला। भारत तकनीकी एवं रक्षा उत्पादन में चौथे स्थान पर खड़ा है। इन सभी के बावजूद वर्ष 2025 में ही पाकिस्तान की आतंकी साजिश का शिकार कश्मीरी पर्यंटन विभाग को भी नहीं भूला जा सकता। पाकिस्तान ने जब देखा कि कश्मीर में लगातार पर्यंटकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है तो उसने पहलगाम में पर्यंटकों पर हमला करा दिया इससे 25 लोग मारे गए। आतंकी हमले तो असंख्य वार हुए हैं कश्मीर में किन्तु 1989 के बाद यह पहली बार हुआ है जब धर्म पूछकर पर्यंटकों को गोली मारी गई। इसी वजह से पाकिस्तान की इस हरकत से भारत में अत्यन्त आव्रोश व्याप्त हो गया। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिन्दूर चलाकर पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने तब खुल गई जब आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के राजनेता और शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। पाकिस्तान अपने देश के आतंकी ठिकानों को अपने लिए घातक नहीं मानता। इस्लामाबाद का मानना है कि जितने भी आतंकी गिरोह हैं वे सभी पाकिस्तान के लिए हीरों हैं। दुनिया की हर सेना में तीन विग होती हैं किन्तु पाकिस्तान में 4 होती हैं। चौथी शाखा फिदायीन की होती है और उनकी भता, ट्रेनिग तथा ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्हीं आतंकी संगठनों की होती हैं जिन्हें पाकिस्तान की फौज मोटी वित्तीय मदद करती है। पाकिस्तान बारबार एफएटीएफ की ग्रो लिस्ट में शामिल होता है फिर दो-एक सरगना को हाउस अरेस्ट करके इस बात का दिखावा करता है कि वह अब आतंकियों को नियंत्रित करेगा और वुछ समय बाद फिर से आतंकियों का वित्त पोषण शुरू कर देता है। 2025 में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसके तमाम सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। पाकिस्तान ने भी चीनी की मदद से भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया किन्तु एस-400 डिपेंस सिस्टम की मदद से भारत ने शत्रु देश के हर हमलों को असफल करने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया कि भारत के पास अपार रक्षा संसाधन हैं और खुलकर कोई देश अपनी सेना और युद्धक विमान देकर उसकी सहायता नहीं करेगा। लजिस्टिक सपोर्ट तो चीन और तुका दोनों ने दी किन्तु पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि किसी देश ने युद्धक पाकिस्तान की वैसी मदद नहीं की जैसा कि वह चाहता था। बहरहाल 2025 में भारत और पाक ने एक-दूसरे की क्षमता का एहसास किया। लेकिन दोनों ने समझदारी दिखाकर युद्ध को 48 घंटे में ही समाप्त करके बहुत समझदारी का काम किया अन्यथा यदि दोनों देश युद्ध में पंस जाते तो दोनों देशों का ही बंटाधार होता। बहरहाल वर्ष 2025 में ही अन्य आतंकी घटनाओं में लालकिले का हमला भी शामिल था जिसमें लोगों की जान बचाने वाले ईश्वर का दूसरा रूप माने जाने वाले डाक्टर ही बारूदी खेल में शामिल थे। इसके अलावा तमाम दुर्घटनाएं हुईं। 2025 भारत का अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर संबंधों में तनाव के लिए भी जाना जाएगा। किन्तु इन सभी अशुभ घटनाओं का अंधेरी रात के बाद सवेरा होना निाित है इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्ष 2026 सुखद, समृद्ध और सशक्त भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए माना जाए। दुनिया में जितने भी देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वे संयम और समझ से काम लेंगे और विश्व बंधुत्व के महत्व को महसूस करेंगे तभी "सव्रे भवन्तु सुखिनः सव्रे सन्तु निरामयाः"

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में बीओटी मोड पर 374 किलोमीटर लंबे और 19,142 करोड़ रुपये की लागत वाले 6 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण वाली परियोजना को मंजूरी दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज महाराष्ट्र में बीओटी मोड पर 374 किलोमीटर लंबी और 19,142 करोड़ रुपये की कुल लागत से निर्मित होने वाली छह लेन की ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना नासिक, अहिल्यानगर और सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों को कुरनूल से जोड़ेगी, जैसा कि मानचित्र में दशार्या गया है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सिद्धांत के तहत एकीकृत परिवहन अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

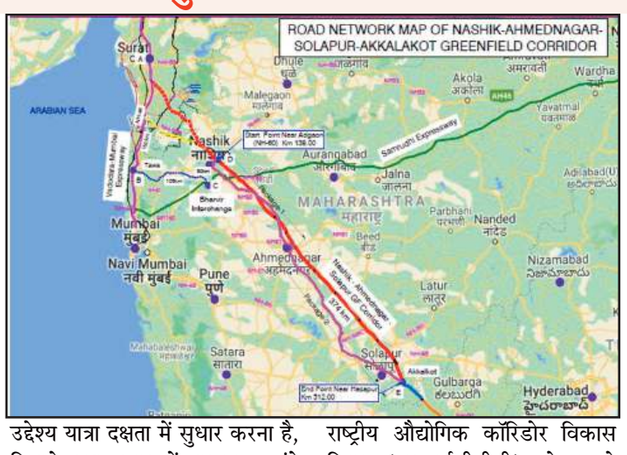

नासिक से अक्कलकोट तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को वधावन बंदरगाह इंटरचेंज के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, नासिक में एनएच-60 (अदेगांव) के जंक्शन पर आगरा-मुंबई कॉरिडोर और पांगरी (नासिक के पास) में समृद्धि महामार्ग से जोड़ा जाना है। प्रस्तावित कॉरिडोर पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। चेन्नई बंदरगाह से की ओर से तिरुवल्लूर, रेनिगुंटा, कडप्पा और कुरनूल होते हुए चेन्नई से हसापुर (महाराष्ट्र सीमा) तक लगभग 4-लेन कॉरिडोर परियोजनाएं (700 किमी लंबा) पहले से ही निमार्णाधीन है। प्रस्तावित एक्सेस-नियंत्रित छह-लेन ग्रीनफील्ड परियोजना कॉरिडोर का प्राथमिक

उद्देश्य यात्रा दक्षता में सुधार करना है, जिससे यात्रा समय में लगभग17 घंटे की कमी और यात्रा दूरी में 201 किमी की कमी होने की उम्मीद है। नासिक-अक्कलकोट (सोलापुर) कनेक्टिविटी कोप्पार्थी और ओरवाकल के प्रमुख राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (एनआईसीडीसी) नोड्स से शुरू और समाप्त होने वाले माल ढुलाई के लिए लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करेगी। इस खंड का नासिक-तलेगांव दिघे वाला हिस्सा पुणे-नासिक एक्सप्रेसवे के विकास की आवश्यकता को भी पूरा करता है, जिसे एनआईसीडीसी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में चिह्नित किया है। यह परियोजना बेहतर सुरक्षा और निर्बाध यातायात आवागमन के लिए डिजाइन किया गया एक उच्च गति कॉरिडोर प्रदान करती है, जिससे यात्रा का समय, भीड़भाड़ और परिचालन लागत कम होती है। इस परियोजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना से क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बेहतर होगा, जिससे नासिक, अहिल्यानगर, धराशिव और सोलापुर जिलों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

यह छह लेन का एक्ॅ सेस-कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर क्ॅ लोज टोलिंग प्रणाली के साथ विकसित किया गया है, जो औसतन 60 किमी/घंटे की वाहन गति तथा 100 किमी/घंटे की डिजाइन गति को समर्थन देगा। इससे कुल यात्रा समय लगभग 17 घंटे तक कम हो जाएंगा (31 घंटे का 55 प्रतिशत रह जाएगा), साथ ही यात्री और मालवाहक दोनों वाहनों के लिए सुरक्षित, तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

इस परियोजना से लगभग 251.06 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 313.83 लाख मानव-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। इसके अलावा, प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

ओडिशा में एनएच-326 के 68,600 किलोमीटर से 311,700 किलोमीटर तक मौजूदा 2-लेन सड़क को पक्की शोल्डर सहित 2-लेन सड़क में बदलने के लिए 1526.21 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी मोड पर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने ओडिशा में एनएच-326 के 68,600 किलोमीटर से 311,700 किलोमीटर तक मौजूदा 2-लेन सड़क को पक्की शोल्डर सहित 2-लेन सड़क में बदलने के लिए 1526.21 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी मोड पर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी

प्रविष्टि तिथिः 31 ञ्एड 2025 3:14ढट्ु८ ढक्ष ऊै

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ओडिशा राज्य में एनएच-326 के 68,600 किलोमीटर से 311,700 किलोमीटर तक मौजूदा 2-लेन को पेव्ड शोल्डर (सड़क के किनारे बनी पक्की, समतल पट्टी) सहित 2-लेन में बदलने और मजबूत करने को एनएच(ओ) के तहत ईपीसी मोड (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन परियोजना वितरण पद्धति) की मंजूरी दी।

वित्तीय निहितार्थः

इस परियोजना की कुल पूंजी लागत 1,526.21 करोड़ रुपये है। इसमें 966.79 करोड़ रुपये की सिविल निर्माण लागत शामिल है।

फायदेः

एनएच-326 के उन्नयन से यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय हो जाएगी। इससे दक्षिणी ओडिशा का समग्र विकास होगा, विशेष रूप से गजपति, रायगड़ा और कोरापुट जिलों को लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय समुदायों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और पर्यटन केंद्रों को बाजारों, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। इससे क्षेत्र के समावेशी विकास में योगदान मिलेगा।

विवरणः

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-326) का मोहना-कोरापुट खंड (मध्यवर्ती लेन/दो लेन, कई दोषपूर्ण मोड़ और तीव्र ढलान) के कारण वर्तमान में निम्न गुणवत्ता का है। इसका मौजूदा सड़क संरेखण, मार्ग की चौड़ाई और ज्यामितीय कमियां भारी वाहनों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही में बाधा डालती हैं। इसके कारण तटीय बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों तक माल ढुलाई प्रभावित होती है। कॉरिडोर को दो लेन में अपग्रेड करके, पेव्ड शोल्डर बनाकर, ज्यामितीय सुधार (मोड़ का पुनर्संरेखण और ढलान में सुधार), ब्लैक स्पॉट को हटाकर और सड़क को मजबूत करके इन बाधाओं को दूर किया जाएगा। इससे माल और यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही संभव होगी और वाहन संचालन लागत में कमी आएगी।

इसके उन्नत किये जाने से मोहना-कोरापुट से प्रमुख आर्थिक और साजो-सामान गलियारे तक सीधी और बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। यह जो एनएच-26, एनएच-59, एनएच-16 और रायपुर-विशाखापत्तनम गलियारे से जुड़ेगी और गोपालपुर बंदरगाह, जेपोर हवाई अड्डे और कई रेलवे स्टेशनों तक सबके लिए पहुंच में सुधार करेगी। यह कॉरिडोर महत्वपूर्ण औद्योगिक और साजो-सामान केंद्रों (जेके पेपर, मेगा फूड पार्क, नालको, आईएमएफए, उत्कल एल्युमिना, वेदांता, एचएएल) और शिक्षा/पर्यटन केंद्रों (ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट मेडिकल कॉलेज, तप्तपानी, रायगड़ा) को जोड़ता है। इससे माल ढुलाई में तेजी आएगी, यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना दक्षिणी ओडिशा (गजपति, रायगड़ा और कोरापुट जिले) की है और इससे वाहनों की आवाजाही को तेज और सुरक्षित बनाकर राज्य के भीतर और अंतर-राज्यीय संपर्क को काफी हद तक सुधारने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह परियोजना औद्योगिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा देगी तथा आकांक्षी और आदिवासी क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच में सुधार करेगी। आर्थिक विश्लेषण से पता चलता है कि परियोजना का ईआईआरआर 17.95 प्रतिशत (आधार स्थिति) है, जबकि वित्तीय प्रतिफल (एफआईआरआर) नकारात्मक (-2.32 प्रतिशत) है। यह आर्थिक मूल्यांकन में शामिल सामाजिक और गैर-बाजार लाभों को दशार्ता है। इसमें मुख्य रूप से यात्रा समय और वाहन परिचालन लागत में बचत तथा सुरक्षा लाभ (ज्यामितीय सुधारों के बाद मोहना और कोरापुट के बीच लगभग ढाई से तीन घंटे तक की अनुमानित यात्रा समय में बचत और लगभग 12.46 किमी की दूरी की बचत) शामिल हैं।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्यः

यह कार्य ईपीसी मोड में पूरा किया जाएगा। ठेकेदारों को पुख्ता निर्माण और गुणवत्ता आश्वासन प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा। इनमें पूर्वनिर्मित बॉक्स-प्रकार संरचनाएं और पूर्वनिर्मित नालियां, पुलों और ग्रेड विभाजकों के लिए पूर्वनिर्मित आरसीसी/पीएससी गर्डर, प्रबलित मिट्टी की दीवारों पर पूर्वनिर्मित क्रैश बैरियर और फ्रिक्शन स्लैब और फुटपाथ परतों में सीमेंट ट्रीटेड सब-बेस (सीटीएसबी) शामिल किये जा सकते हैं। गुणवत्ता और प्रगति का सत्यापन नेटवर्क सर्वे व्हीकल (एनएसवी) और आवधिक ड्रोन-मैपिंग जैसे विशेष सर्वेक्षण और निगरानी उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा। दैनिक पर्यवेक्षण नियुक्त प्राधिकरण अभियंता द्वारा किया जाएगा और परियोजना की निगरानी परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) के माध्यम से की जाएगी।

प्रत्येक पैकेज के लिए निर्धारित तिथि से 24 महीनों में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद पांच वर्ष की दोष दायित्व/रखरखाव अवधि होगी (कुल अनुबंध अवधि 7 वर्ष की होगीः 2 वर्ष निर्माण + 5 वर्ष दोष दायित्व/रखरखाव)। वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त होने और आवश्यक भूमि पर कब्जा मिलने के बाद अनुबंध प्रदान किया जाएगा।

रोजगार सृजन की क्षमता सहित प्रमुख प्रभावः

इस परियोजना का उद्देश्य यातायात की सुगम और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना तथा ओडिशा के दक्षिणी और पूर्वी भागों के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है। विशेष रूप से गजपति, रायगढ़ा और कोरापुट जिलों को राज्य के शेष भाग और पड़ोसी आंध्र प्रदेश से जोड़ना इसका लक्ष्य है। बेहतर सड़क नेटवर्क से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी तथा दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

निर्माण और रखरखाव अवधि के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों से कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। यह परियोजना निर्माण

ईएसआईसी ने नियोक्ताओं को पिछली देनदारियों के बिना शामिल होने के लिए अधिक समय दिया

-2025 की समय सीमा 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गईः स्प्री-2025 में एक महीने का विस्तार ईएसआईसी के समावेशी और सरलीकृत अनुपालन के प्रयासों को और मजबूत करता है

(जीएनएस)।

नियोक्ताओं, नियोक्ता संघों और राज्य सरकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहन देने की योजना स्प्रीझ2025 (एसपीआरईई 2025), को ईएसआईसी द्वारा शुरू किया गया था। इसके संचालन की अवधि 1 जुलाई, 2025 से 31 दिसंबर तक थी। अब इसे 01.01.2026 से 31.01.2026 तक एक महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

एसपीआरईई योजना को शिमला में आयोजित ईएसआई निगम की 196वीं बैठक में मंजूरी दी गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। इस योजना का उद्देश्य ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना है। यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को बिना किसी निरीक्षण या पूर्व बकाया या रिकॉर्ड की मांग का सामना किए ईएसआई सुविधाओं का लाभ लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।

इस विस्तार के साथ, नियोक्ताओं को ईएसआईसी, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टलों के माध्यम से अपने व्यवसायों और कर्मचारियों को डिजिटल रूप से पंजीकृत करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा। जो प्रतिष्ठान पहले पंजीकृत नहीं थे, उन्हें भी नई समयसीमा के भीतर पंजीकरण कराने पर 'पिछली अंशदान की मांग नहीं', निरीक्षण नहीं और पूर्व अभिलेखों की आवश्यकता नहीं होने का लाभ मिलेगा। यदि नियोक्ता एसपीआरईई योजना का लाभ उठाने में विफल रहता है और ईएसआई योजना के तहत अपने प्रतिष्ठान को पंजीकृत नहीं कराता है, तो ऐसे प्रतिष्ठान को 31.01.2026 के बाद कानूनी कार्रवाई और जुमार्ने के अलावा हजार्ना और ब्याज सहित पिछली अंशदान राशि का भुगतान करना होगा।

स्प्री-2025 को 31 जनवरी, 2026 तक विस्तारित करना भारत में स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए ईएसआईसी की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। यह हाल ही में लागू की गई सामाजिक सुरक्षा संहिता के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है।

भारत ने वेव्स 2025 की मेजबानी की; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इस अग्रणी पहल में 90 से अधिक देश शामिल हुए

वर्षांत समीक्षा 2025 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

क्रिएटोस्फीयर में 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस' - विभिन्न देशों के रचनाकारों को जोड़ना

वेवएक्ॅ स 2025: मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक अगली पीढ़ी का मंच

वेव्ॅ स बाजार, भारत की रचनात्मक प्रतिभाओं और उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला एक ही स्थान पर सभी उत्पादों का पोर्टल

रचनात्मक प्रौद्योगिकियों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण के लिए आईआईसीटी ने नया राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया

(जीएनएस)।

वेव्स : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2025 में भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें कीं। इनमें सबसे बड़ी पहल विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्ॅ स) 2025 था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्ॅ द्र मोदी ने वेव्ॅ स को महज एक आयोजन नहीं, बल्कि "संस्कृति, रचनात्मकता और सार्वभौमिक जुड़ाव की लहर" बताया और दुनिया भर के रचनाकारों को "बड़े सपने देखने और अपनी कहानी कहने" के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने "भारत में सृजन करो, दुनिया के लिए सृजन करो" के भारत के दृष्टिकोण पर भी जोर दिया और वैश्विक निवेशकों और युवाओं को भारत के विशाल रचनात्मक तंत्र से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया।

पीएलआई योजना ने 35,657 करोड़ रुपये के निवेश और 2,321.94 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन राशि के वितरण के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं

(जीएनएस)।

देश में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों में देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव-ऑटो योजना (पीएलआई ऑटो) शुरू की गई है। इस योजना का कुल बजटीय आवंटन 25,938 करोड़ रुपये है। यह वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि को कवर करती है।

पीएलआई-ऑटो योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 पहला प्रदर्शन वर्ष था तथा वित्त वर्ष 2024-25 में चार (4) अनुमोदित आवेदकों को 322 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई (अनुलग्नक की तालिका 1)।

आज तक, प्रदर्शन वर्ष 2024-25 के लिए कुल 1,999.94 करोड़ रुपये की राशि पांच (5) स्वीकृत आवेदकों को वितरित की जा चुकी है।

इस योजना के अंतर्गत कुल 10,42,172 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2डब्ल्यू), 2,38,385 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (ई-3डब्ल्यू), 79,540 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (ई-4डब्ल्यू) और 1,391 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं (अनुलग्नक की तालिका 2)।

पीएलआई ऑटो योजना केवल उन्हीं उत्पादों को प्रोत्साहन देती है जो न्यूनतम 50 प्रतिशत का घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करते हैं। आज तक, चैंपियन ओईएम श्रेणी के अंतर्गत आठ (8) आवेदकों को 94 वेरिएंट के लिए घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जबकि कंपोनेंट चैंपियन श्रेणी के अंतर्गत दस (10) आवेदकों को 37 वेरिएंट के लिए घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणन प्राप्त हुआ है (अनुलग्ॅ नक की तालिका 3 और 4)। पीएलआई ऑटो के आवेदक प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस योजना के अंतर्गत, 30 सितम्बर, 2025 तक 35,657 करोड़ रुपये का संचयी निवेश और 32,879 करोड़ रुपये की संचयी निर्धारित बिक्री की गई है। इसके अलावा, 48,974 लोगों के लिए रोजगार सृजित किया गया है। 31 दिसंबर, 2025 तक 2,321.94 करोड़ रुपये का संचयी प्रोत्साहन वितरित किया जा चुका है

उत्तराखंड मौसम : क्या नए साल में होगा बर्फबारी से स्वागत, कहां और कब, जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी

(जीएनएस)।

उत्तराखंड में नए साल का स्वागत कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी से हो सकता है। इस समय सबसे ज्यादा पर्यटक पहाड़ों की तरफ पहुंच रहे है। नए साल के जश्न के लिए टूरिस्ट प्लेस पैक हो गए हैं। सबको बर्फबारी का इंतजार है। बुधवार को मौसम सुबह से बदला हुआ नजर आया।

एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है, जिससे प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर से राज्य के उच्च हिमालयी जिलों-उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़-में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

इसके साथ ही गढ़वाल मंडल के अन्य क्षेत्रों जैसे देहरादून के पर्वतीय इलाके, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जनपदों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3200 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना अधिक है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड और बढ़ सकती है। वहीं एक जनवरी को कुमाऊँ मंडल के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 3000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। नए साल की शुरूआत के साथ पहाड़ों में मौसम सुहावना लेकिन ठंडा रहने का अनुमान है।

दो जनवरी से मौसम की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना जताई गई है। इस दिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा मैदानी इलाकों-विशेषकर हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर-में घने कोहरे की आशंका बनी रहेगी, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है।

आने वाले दो दिनों में प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।

वित्त मंत्रालय की वर्ष 2025 के लिए वर्षान्त समीक्षाः लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

(जीएनएस)।

2025 में, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यान्वयन और पॉलिसी पहलों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कीं।

2025 के दौरान उपलब्धियों का एक प्रमुख आकर्षण चुने गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य संगठनों के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की सजग निगरानी और सुविधा थी। चुने गए सीपीएसई (जिनका सालाना कैपेक्स अनुमान ₹100 करोड़ या उससे अधिक है) और अन्य सरकारी संगठनों - जैसे रेलवे बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी), और दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) - के लिए कैपेक्स सफलता को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सितंबर 2025 के अंत तक इकट्ठा किया गया है। अप्रैल-सितंबर 2025 की अवधि के दौरान, इन संस्थाओं ने ₹3.85 लाख करोड़ का कैपेक्स प्राप्त किया, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹7.85 लाख करोड़ के वार्षिक बजट अनुमानों का 49.1% है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसई के लिए एक साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वर्कशॉप की एक सीरीज आयोजित करने की पहल की है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल के अंतिम दिन महाराष्ट्र में किसानों से किया संवाद और नए साल के पहले दिन ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद

साल के अंतिम दिन केन्द्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से किया संवाद
नए वर्ष के पहले दिन शिवराज सिंह करेंगे ग्रामीणों से चर्चा
कृषि- किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

(जीएनएस)।

नई दिल्ली- केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र प्रवास के दौरान अहिल्यानगर के बालेश्वर में कृषि विकास केन्द्र का भ्रमण कर किसानों से संवाद किया। शिवराज सिंह ने साल के अंतिम दिन खेत-खलिहान से जुड़े मुद्दों पर

किसानों के साथ संवाद करते हुए केन्द्रीय मंत्री हितग्राहियों को हितलाभ

कहा कि, केंद्र सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। साथ ही भी वितरित किए।

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और किसान उसके प्राण। किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। शिवराज सिंह ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

साल के पहले दिन करेंगे ग्रामीणों से चर्चा

वहीं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नए साल के पहले दिन, 1 जनवरी को ग्राम लोणी बुदरुक में ग्राम सभा कार्यक्रम में शामिल होंगे और ग्रामीणों से संवाद करेंगे, जहां गांवों के विकास, रोजगार, कृषि, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विषयों पर केन्द्रीय मंत्री चर्चा करेंगे।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने भारत सरकार के कैलेंडर 2026 का अनावरण किया

कैलेंडर का विषय है "भारत@2026: सेवा, सुशासन और समृद्धि"
सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू ने कहा कि भारत@2026 कैलेंडर भारत की बदलती तस्वीर को प्रदर्शित करता है

(जीएनएस)।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज भारत सरकार के कैलेंडर 2026 का अनावरण किया। इस अवसर पर डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि यह कैलेंडर केवल तारीखों और महीनों का वार्षिक प्रकाशन मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो भारत की परिवर्तनकारी यात्रा को दशार्ता है, गवर्नेंस की प्राथमिकताओं को उजागर करता है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हमारे सामूहिक संकल्प को नया उत्साह प्रदान करता है।

कैलेंडर का विषय "भारत@2026: सेवा, सुशासन और समृद्धि", एक ऐसे भारत को प्रस्तुत करता है जो अपनी पहचान के प्रति सुरक्षित है, अपनी संस्थाओं में मजबूत है और अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण में स्पष्ट है। डॉ. एल. मुरुगन ने इस बात पर जोर दिया कि यह कैलेंडर देश के आत्मविश्वास की उस भावना को दशार्ता है, जो जन-केंद्रित शासन, मजबूत सर्विस डिलीवरी और उन सुधारों पर आधारित है जिन्हें प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नागरिकों एवं सरकार के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

वर्ष 2025 में किए गए प्रमुख सुधारों का उल्लेख करते हुए, डॉ. मुरुगन ने कहा कि संरचनात्मक उपायों ने भारत की आर्थिक मजबूती को बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने उल्लेख किया कि नई कर व्यवस्था के तहत कर राहत, जीएसटी 2.0 को सरल बनाने, चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन और केंद्रित रोजगार सृजन पहल ने उत्पादकता, जीवन की सुगमता और समावेशी समृद्धि को गति प्रदान की है।

इस अवसर पर बोलते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, श्री संजय जाजू ने कहा कि भारत सरकार का कैलेंडर वास्तव में सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है और यह एक शक्तिशाली संचार माध्यम के रूप में विकसित हुआ है, जो राष्ट्र की प्राथमिकताओं और मूल्यों को दशार्ता है।

आर्मी हॉस्पिटल (आर एंड आर) भारत में आईस्टेंट के साथ पहली 3डी फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी की

(जीएनएस)।

दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) के नेत्र रोग विभाग ने भारतीय चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए उन्नत इमेजिंग तकनीक और न्यूनतम चीर-फाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी को मिलाकर भारत में पहली बार आईस्टेंट के साथ 3डी फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक संपन्न की है। नए स्टैंड-माउंटेड स्पेक्ट्रालिस सिस्टम और अत्याधुनिक 3डी ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से संचालित यह अभूतपूर्व प्रक्रिया सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं को वैश्विक नेत्र चिकित्सा देखभाल में अग्रणी स्थान पर रखती है।

ग्लूकोमा, जो अपूरणीय अंधापन का एक प्रमुख कारण है, अपनी धीमी प्रगति के कारण लंबे समय से चिकित्सकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यह अभूतपूर्व तकनीक जलीय द्रव प्रवाह मार्गों का अभूतपूर्व वास्तविक समय दृश्य प्रदान करती है, जिससे सर्जन सटीक और लक्षित उपचार कर सकते हैं और रोगियों के उपचार में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं।

देश में अपनी तरह की पहली पहल के रूप में न्यूनतम चीर-फाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी, आईस्टेंट के साथ 3डी फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी का एकीकरण ग्लूकोमा के उपचार में एक नया मानदंड स्थापित करता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान बेहतर इमेजिंग और दीर्घकालिक बेहतर परिणाम सुनिश्चित होते हैं। सशस्त्र बलों के लिए यह न केवल एक चिकित्सा उपलब्धि है बल्कि दृष्टि सुरक्षा और परिचालन तत्परता में एक रणनीतिक छलांग भी है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने त्वरित अंतराल में दो प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन-डीआरडीओ ने 31 दिसंबर, 2025 को दिन में लगभग 10 बजकर तीस मिनट पर ओडिशा तट के पास एक ही लॉन्चर से दो प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया। ये परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन के तहत किए गए। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के ट्रैकिंग सेंसरों से पुष्टि हुई कि दोनों मिसाइलों ने निर्धारित पथ का अनुसरण कर सभी उड़ान उद्देश्यों को पूरा किया। प्रक्षेपण बिंदुओं के निकट तैनात जहाज पर लगे टेलीमेट्री सिस्टम से भी इसकी पुष्टि हुई।

प्रलय स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें उच्च भेदक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन तकनीक का उपयोग किया गया है। यह मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों तक कई प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है।

प्रलय मिसाइल को मिसाइल प्रणाली और वैमानिकी के उन्नत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं (रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला, शस्त्र अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (इंजीनियर) और एकीकृत परीक्षण रेंज), विकास-सह-उत्पादन साझेदारों (भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है। परीक्षणों के लिए, दोनों विकास-सह-उत्पादन साझेदारों ने प्रणालियों को एकीकृत किया। परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के उपयोगकर्ता प्रतिनिधि, और विकास-सह-उत्पादन साझेदारों सहित उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने त्वरित अंतर पर मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण पर डीआरडीओ, भारतीय वायु सेना, भारतीय सेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रलय मिसाइल के साल्वो प्रक्षेपण ने मिसाइल की विश्वसनीयता को स्थापित कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में 'साल्वो लॉन्च' का मतलब होता है. एक साथ या बहुत कम अंतर पर कई हथियारों से हमला।

एमसीए 03 नए क्षेत्रीय निदेशालय (आरडी) और 6 नए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) को नियुक्त करेगा

(जीएनएस)।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के निरंतर प्रयास के अंतर्गत, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय 16 फरवरी, 2026 से 03 क्षेत्रीय निदेशालय (आरडी) और 06 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) खोलेगा। इससे रेगुलेटरी सुविधा मिलेगी और साथ ही तेजी से बढ़ते व्यापार माहौल को जरूरी प्रोत्साहन भी मिलेगा।

मौजूदा उत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशालय, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और जिसके अधिकार क्षेत्र में एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड राज्य और चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उसे दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। आरडी (एनआर-क) का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसके अधिकार क्षेत्र में एनसीटी दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य आएंगे। आरडी (एनआर-क्क) का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा और इसके अधिकार क्षेत्र में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड राज्य और चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आएंगे।

मौजूदा आरओसी, दिल्ली जिसका अधिकार क्षेत्र एनसीटी दिल्ली और हरियाणा में था, उसे 03 आरओसी में बांटा गया है। आरओसी (एनसीटी ऑफ दिल्ली-क) का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली और दिल्ली पूर्व जिलों पर होगा; आरओसी (एनसीटी ऑफ दिल्ली-क्क) का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र सेंट्रल दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली और शाहदरा जिलों पर होगा। आरओसी (हरियाणा), जो चंडीगढ़ में होगा, उसका अधिकार क्षेत्र हरियाणा के सभी जिलों पर होगा झ पहले, आरओसी (दिल्ली) का अधिकार क्षेत्र हरियाणा पर भी था। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश के 17 सबसे पश्चिमी जिलों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला आरओसी, नोएडा मौजूदा आरओसी, कानपुर से अलग किया जा रहा है।

मौजूदा पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशालय, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र, गोवा राज्य और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश पर है, उसे दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। आरडी (डब्ल्यूआर-क) जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा, उसका अधिकार क्षेत्र मुंबई, मुंबई उप शहरी जिलों, गोवा राज्य और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश पर होगा। आरडी (डब्ल्यूआर-क्क) जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में होगा, उसका अधिकार क्षेत्र मुंबई और मुंबई उप शहरी को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी जिलों पर होगा।

मौजूदा आरओसी, मुंबई को 02 आरओसी में बांटा गया है। आरओसी, मुंबई-क का मुख्यालय मुंबई में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र मुंबई और मुंबई उप शहरी जिलों पर होगा। आरओसी, मुंबई-क्क का मुख्यालय नवी मुंबई में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र औरंगाबाद, धुले, जलगांव, नंदुरबार, नासिक, पालघर, रायगढ़ और ठाणे जिलों पर होगा। इसके अतिरिक्त, आरओसी, नागपुर की स्थापना की जा रही है, जिसका अधिकार क्षेत्र विदर्भ के 11 जिलों और मराठवाड़ा क्षेत्र के 7 जिलों पर होगा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र (एसडब्ल्यूआर) के लिए एक नया क्षेत्रीय निदेशालय बनाया गया है, जिसका मुख्यालय बैंगलोर में होगा और इसके अधिकार क्षेत्र में कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश आएंगे।

मौजूदा आरओसी, कोलकाता को 02 आरओसी में बांटा गया है। आरओसी, कोलकाता-क का मुख्यालय कोलकाता में होगा और इसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता जिले और सिक्किम राज्य पर होगा।

भारतीय वायुसेना के उप-प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी सेवानिवृत्त हुए

(जीएनएस)।

एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी 31 दिसंबर 2025 को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के उप वायु सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्होंने राष्ट्र की चार दशकों तक गौरवशाली सेवा की है।

एयर मार्शल तिवारी 7 जून 1986 को भारतीय वायु सेना की लड़ाकू विमान शाखा में फ्लाइंग पायलट के रूप में कमीशन हुए । विभिन्न प्रकार के विमानों पर 3600 घंटे से अधिक के उड़ान अनुभव के साथ, एयर मार्शल ने विविध स्टाफ और कमांड पदों पर कार्य किया है। एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और प्रायोगिक टेस्ट पायलट होने के अलावा, एयर मार्शल अमेरिका के एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के स्नातक हैं। अपने शानदार सैन्य करियर के दौरान, उन्होंने

वेलिंगटन में भारतीय वायु सेना के टेस्ट पायलट स्कूल और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में डायरेक्टिंग स्टाफ के रूप में कार्य किया। उनके व्यापक फील्ड अनुभव में विभिन्न हथियारों और प्रणालियों का परिचालन परीक्षण शामिल है, जिसमें 1999 में कारगिल ऑपरेशन के दौरान 'लाइटनिंग' लेजर डेजिग्नेशन पॉड का संचालन भी शामिल है। वे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उड़ान परीक्षण के विभिन्न चरणों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। एयर मार्शल ने 2013 से 2016 तक पेरिस में एयर अताशे के रूप में कार्य किया। भारतीय वायु सेना में अपने करियर के दौरान, उन्होंने सहायक चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (प्रोजेक्ट्स), सहायक चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (प्लान्स), एयर हेडक्वार्टर (वीबी) में डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पदों पर कार्य किया।

उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में, एयर मार्शल तिवारी को परम विशिष्ट सेवा पदक (2025), अति विशिष्ट सेवा पदक (2022) और वायुसेना पदक (2008) से सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 में संचालन में विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से अलंकृत किया गया।

भारत सरकार के खातों की वित्त वर्ष 2025-26 के नवंबर माह तक की मासिक समीक्षा

(जीएनएस)।

भारत सरकार के नवंबर 2025 तक के मासिक खातों का संकलन कर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

सरकार को नवंबर 2025 तक 19,49,239 करोड़ रुपए (वर्ष 2025-26 के संबंधित वर्ष की कुल प्राप्तियों का 55.7 प्रतिशत) प्राप्त हुए हैं, जिसमें 13,93,946 करोड़ रुपए कर राजस्व (केंद्र को प्राप्त शुद्ध राशि), 5,16,366 करोड़ रुपए गैर-कर राजस्व और 38,927 करोड़ रुपए गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को करों में हिस्सेदारी के रूप में 9,36,561 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,24,498 करोड़ रुपए अधिक है।

भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 29,25,910 करोड़ रुपए (वर्ष 2025-26 के संबंधित बजट अनुमान का 57.8 प्रतिशत) है। इसमें से 22,67,700 करोड़ रुपए राजस्व मद के अंतर्गत तथा 6,58,210 करोड़ रुपए पूंजीगत मद के अंतर्गत व्यय किए गए है। कुल राजस्व व्यय में से 7,45,765 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान के रूप में तथा 2,88,333 करोड़ रुपए प्रमुख सब्सिडी के मद में व्यय किए गए है।

वर्ष 2025 की समीक्षा: वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक नेतृत्व को समर्पित वर्ष

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रमुख पहलें, सुधार और उपलब्धियां

1. वन संरक्षण, वृक्षारोपण और हरित आवरण संवर्धन

1.1 एक पेड़ मां के नाम अभियान

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान विश्व के सबसे बड़े जन-केंद्रित पर्यावरण आंदोलनों में से एक बनकर उभरा। इसे सरकार और समाज के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।

24 दिसंबर 2025 तक 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए।

इस अभियान में भावनात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों को एकीकृत किया गया।

मेरी लाइफ पोर्टल के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को डिजिटल रूप से ट्रैक किया गया।

1.2 वन और वृक्ष आवरण की स्थिति

भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के अनुसार:

देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत भाग वनों और वृक्षों से आच्छादित है (जिसमें 21.76 प्रतिशत वन क्षेत्र और 3.41 प्रतिशत वृक्ष क्षेत्र शामिल हैं)।

वर्ष 2013 से अब तक वन और वृक्ष आवरण में कुल मिलाकर 4.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एफएओ के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार:

ध भारत वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर है (पहले 10वें स्थान पर था)।

ध वार्षिक शुद्ध वन वृद्धि में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान बरकरार रखता है।

ये उपलब्धियां वनों की गुणवत्ता में सुधार करते हुए हरित आवरण को बढ़ाने के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

1.3 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय सीएएमपीए)

राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण ने अपनी नीतियों और नवोन्मेषी डिजिटल सुधारों के माध्यम से भारत में क्षतिपूर्ति वनीकरण और इको-सिस्टम सेवाओं की बहाली की गतिविधियों की योजना और प्रबंधन में परिवर्तन किया है।

मजबूत वित्तीय तंत्र, बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक बहाली और नई डिजिटल प्रणालियों को मिलाकर—जैसे कि (1) अखिल भारतीय डिजिटल एपीओ पोर्टल को शुरू करना, (2) बीआईएसएजी-एन के साथ संयुक्त रूप से निगरानी और मूल्यांकन उपकरण का विकास, और (3) राष्ट्रीय कैम्पा डैशबोर्ड—राष्ट्रीय सीएएमपीए पारदर्शिता, जवाबदेही और वैज्ञानिक निरीक्षण सुनिश्चित कर रहा है।

राष्ट्रीय प्राधिकरण सीएएमपीए ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 8561.34 करोड़ रुपये की वार्षिक परिचालन योजना को मंजूरी दे दी है ।

1.4 अरावली भूदृश्य बहाली (ग्रीन वॉल पहल)

अरावली ग्रीन वॉल पहल के तहत 6.31 मिलियन हेक्टेयर भूमि के पुनर्स्थापन का प्रस्ताव है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप क्षेत्र शामिल हैं।

एक चरणबद्ध पुनर्स्थापन योजना (2025-2034) सीएएमपीए, एमजीएनआरईजीएस, ग्रीन इंडिया मिशन और अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय के माध्यम से वन पुनर्स्थापन, घास के मैदानों के पुनरुद्धार और खदानों के पुनर्ग्रहण पर केंद्रित है।

2025 तक लगभग 36,025 हेक्टेयर क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया जा चुका है।

अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चार राज्यों में फैली 435 नर्सरियां स्थापित की गई हैं, जिनकी संयुक्त अनुमानित उत्पादन क्षमता 393.24 लाख पौधों की है।

अरावली पर्वत श्रृंखला को पुनर्स्थापित करने की एक प्रमुख पहल, अरावली भूदृश्य बहाली के लिए एक विस्तृत कार्य योजना का अनावरण 21 मई 2025 को किया गया। यह कार्य योजना अरावली की पारिस्थितिक अखंडता को बहाल करने के लिए विज्ञान-आधारित, समुदाय-नेतृत्व वाली और नीति-समर्थित कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

2. वन्यजीव संरक्षण और प्रजाति पुनर्प्राप्ति

2.1 प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट

भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण कार्यक्रमों को और मजबूत करने की नीति को जारी रखा:

अब 58 टाइगर रिजर्व लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जबकि 2014 में इनकी संख्या 46 थी।

नया अभ्यारण्य: माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश।

अखिल भारतीय बाघ आकलन का छठा चक्र शुरू किया गया (वैश्विक स्तर पर पहली बार)।

पयार्वास सुधार और गलियारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई।

हाथी अभ्यारण्यों की संख्या 2014 में 26 की तुलना में 2025 में बढ़कर 33 हो गई; लगभग 8,610 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षण के अंतर्गत लाया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 जनवरी 2026 को पिपरावा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे

'लोटस लाइट: रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन' में प्रत्यावर्तित अवशेषों और संबंधित प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय "लोटस लाइट: रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन" शीर्षक से एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जिसमें पूजनीय पिपरावा अवशेषों के साथ-साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी बुद्ध की शिक्षाओं के साथ भारत के अटूट सभ्यतागत संबंध और अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और प्रस्तुति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित राय पिथोरा सांस्कृतिक परिसर में किया जाएगा। यह आयोजन भारत के सांस्कृतिक और राजनयिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि प्रदर्शित अवशेषों में अत्यधिक ऐतिहासिक, पुरातात्विक और आध्यात्मिक महत्व के प्रत्यावर्तित पवित्र अवशेष शामिल हैं, जिनका विश्व भर के बौद्ध समुदायों द्वारा सम्मान किया जाता है।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खोजे गए पिपरावा अवशेषों को व्यापक रूप से गौतम बुद्ध के पार्थिव अवशेषों से संबंधित माना जाता है, जिन्हें शाक्य वंश द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। इनका प्रत्यावर्तन और सार्वजनिक प्रदर्शन भारत द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने और बुद्ध की शिक्षाओं में निहित शांति, करुणा और ज्ञान के सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों को दशार्ता है।

इस प्रदर्शनी में शामिल होंगी:

पवित्र पिपरावा अवशेष और संबंधित प्राचीन वस्तुएं

इनके ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक संदर्भों को उजागर करने वाली सुनियोजित प्रदर्शनियां

भारत को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल बताते हुए व्याख्यात्मक कथाए

यह प्रदर्शनी विद्वानों, भक्तों और आम जनता सभी के लिए सोच-समझकर तैयार की गई है।

गांधी सभागार में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की जनपदीय समिति बैठक संपन्न

(जीएनएस)।

पीलीभीत,गांधी सभागार में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जनपदीय अनुश्रवण व पर्यवेक्षण समिति की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस बैठक का उद्देश्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति वितरण तथा शुल्क प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना था।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने योजना की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक जिले के हजारों दशमोत्तर छात्रों को लाभ पहुंचाया गया है। समिति सदस्यों ने विभिन्न ब्लाकों से प्राप्त शिकायतों का निपटारा किया तथा लंबित मामलों को शीघ्र हल करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदनों की जांच तेज करने पर बल दिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनपद स्तर पर नियमित अनुश्रवण के लिए मासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही, स्कूलों एवं महाविद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र छात्रों को योजना से जोड़ा जाएगा। समिति ने पारदर्शिता बनाए रखने हेतु डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने का सुझाव दिया।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर, शिक्षा विभाग के अधिकारी, एनजीओ प्रतिनिधि तथा अभिभावक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में लिए गए निर्णयों से छात्रों को शीघ्र लाभ मिलेगा तथा शिक्षा का अधिकार मजबूत होगा।

बीसलपुर में अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन, अटल जी के विचारों को किया गया नमन

(जीएनएस)।

बीसलपुर (पीलीभीत)।

विधानसभा क्षेत्र बीसलपुर के विकास खंड बीसलपुर में भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अटल जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के ऐसे शिखर पुरुष थे, जिन्होंने सुशासन, राष्ट्रवाद और विकास की नई परिभाषा गढ़ी। उनके आदर्श आज भी युवाओं और जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय महामंत्री राकेश कुमार मिश्र 'अनावा', बीसलपुर विधायक विवेक कुमार वर्मा, जिला महामंत्री अमित अग्रवाल, जिला मंत्री आयुष मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य रेनू राज, मनोज गुप्ता (जिला संयोजक, व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा पीलीभीत) सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वक्ताओं ने अटल जी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों, उनकी प्रखर वक्तृत्व कला, सरल जीवनशैली और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने अटल जी के विचारों को आत्मसात करने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आयोजन का समापन राष्ट्र निर्माण में सहभागिता और सेवा भाव को आगे बढ़ाने के संदेश के साथ हुआ।

बीसलपुर में अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन, अटल जी के विचारों को किया गया नमन

(जीएनएस)।

बीसलपुर (पीलीभीत)।

विधानसभा क्षेत्र बीसलपुर के विकास खंड बीसलपुर में भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अटल जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के ऐसे शिखर पुरुष थे, जिन्होंने सुशासन, राष्ट्रवाद और विकास की नई परिभाषा गढ़ी। उनके आदर्श आज भी युवाओं और जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय महामंत्री राकेश कुमार मिश्र 'अनावा', बीसलपुर विधायक विवेक कुमार वर्मा, जिला महामंत्री अमित अग्रवाल, जिला मंत्री आयुष मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य रेनू राज, मनोज गुप्ता (जिला संयोजक, व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा पीलीभीत) सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वक्ताओं ने अटल जी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों, उनकी प्रखर वक्तृत्व कला, सरल जीवनशैली और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने अटल जी के विचारों को आत्मसात करने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आयोजन का समापन राष्ट्र निर्माण में सहभागिता और सेवा भाव को आगे बढ़ाने के संदेश के साथ हुआ।

नए साल पर जश्न के दौरान पीलीभीत पुलिस की कड़ी सुरक्षा: हुड़दंगियों पर पैनी नजर, 200+ जवान तैनात

(जीएनएस)।

पीलीभीत:नववर्ष के जश्न के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को पीलीभीत पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक यादव के निर्देश पर जिले भर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। शराबी हुड़दंगियों और छेड़खानी करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

एसपी ने बताया कि प्रमुख पिकनिक स्पॉट, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। नौगवां चौराहा, आसाम चौराहा, डिग्री कॉलेज चौराहा, छतरी चौराहा और सुनहरी मस्जिद चौराहा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त पिकेट तैनात रहेंगे। सादी वर्दी के पुलिसकर्मी भी संदिग्धों पर नजर रखेंगे।

विशेष चेकिंग अभियान 31 दिसंबर शाम से 31 दिसंबर शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक जिले में सघन चेकिंग चलेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबे, धर्मशाला और सिनेमा घरों में संदिग्धों की तलाश की जाएगी। प्रमुख सड़कों पर बैरियर लगाकर वाहनों की जांच होगी। वायरलेस सेट से लैस पुलिस टीमें आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाएंगी।

एसपी अभिषेक यादव ने चेतावनी दी कि जश्न के नाम पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी क्षेत्राधिकारियों (सीओ) और थाना प्रभारियों को यूपी 112 गाड़ियों को भ्रमणशील रखने के निर्देश दिए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने या शोर-शराबा करने वालों को हिरासत में लिया जाएगा।

पुलिस का उद्देश्य है कि नागरिक बिना भय के नए साल का आनंद ले सकें। जनता से अपील है कि शांतिपूर्ण उत्सव मनाएं और संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें।

15 हजार की नगदी सहित जेवरात उठा ले गये चोर

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। बीती रात्रि सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चिलौकी मे छत के सहारे घर मे दाखिल हुए अज्ञात चोरो ने अलमारी मे रखे 15 हजार की नगदी सहित जेवरात उठा ले गये पीड़ित ने रात्रि मे ही पी आर वी व थाना सफदरगंज मे चोरी की जानकारी दी।

ग्राम चिलौकी निवासी राहुल कुमार पुत्र चन्द्रकान्त के घर मध्य रात्रि छत के सहारे दाखिल हुए अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखी सोने की चेन, अंगुठी, मांगबेदी, मंगलसूत्र, झाला, समेत लगभग 150 ग्राम सोना और चांदी पायजेब, बिछिया, खगौरा, कमरपेटी सहित लगभग 500 ग्राम चादी एवं बैग में रखे 15 हजार की नकदी लॉकर तोडकर चोरी कर ले गये । रात्रि करीब ढाई बजे जब राहुल लघुशंका के लिए उठा तो देखा कि कमरे के बक्से में रखा समान बिखरा पड़ा है और अलमारी का दरवाजा लाकर टूटा हुआ है। यह घटना देखकर परिजन बहुत सहम गया और पीआरवी को सूचित किया । मौके पर पहुंची पीआरवी और स्थानीय पुलिस ने पहुंच कर घटना का निरीक्षण किया है।

जगतपुर में दबंगई का मामला उजागर, बिना अनुमति तालाब खाली कराने का आरोप

(जीएनएस)।

पीलीभीत जनपद के जगतपुर गाँव में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रेम कुमार उर्फ ओमकार पर प्रशासनिक अनुमति के बिना तालाब खाली कराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दबंगई के बल पर की गई इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

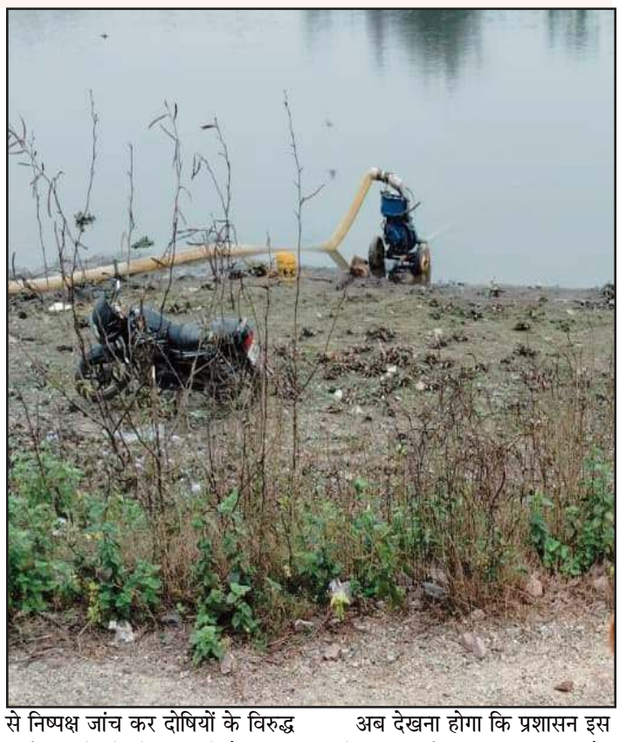

तालाब के खाली हो जाने से न केवल ग्रामीणों की जल आवश्यकताओं पर संकट उत्पन्न हो गया है, बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी पेयजल की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तालाब वर्षों से सार्वजनिक उपयोग में रहा है और इसकी मनमानी तरीके से निकासी नियमों का खुला उल्लंघन है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना किसी वैधानिक अनुमति के तालाब खाली कराए जाने से राजस्व विभाग को भी आर्थिक क्षति पहुंची है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर प्रकरण में क्या कदम उठाता है।

क्रय केंद्र पर किसानों से अवैध वसूली: गन्ना उतार के नाम पर 150 रुपये प्रति ट्रॉली लेने का खुलासा

(जीएनएस)।

पीलीभीत ललित हरी (एलएच) चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र पर किसानों से प्रति ट्रॉली 150 रुपये की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। गन्ना विभाग के औचक निरीक्षण में यह खुलासा हुआ, जिसके बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई।

बिठौरा खुर्द में निरीक्षण :

जिला गन्ना अधिकारी (डीसीओ) खुशीराम भार्गव और वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक रामभद्र द्विवेदी ने मंगलवार को बिठौरा खुर्द द्वितीय स्थित क्रय केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। किसानों ने बताया कि तौल लिपिक प्रेमपाल द्वारा गन्ना उतराई शुल्क के नाम पर 150 रुपये प्रति ट्रॉली वसूले जाते हैं। पैसे न देने पर तौल में बाधा डाली जाती है।

निरीक्षण के दौरान लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया,

लेकिन वह चुप रहा। केंद्र पर 18 दिसंबर से अब तक 15,307.64 क्विंटल गन्ने की खरीद हो चुकी है। शिकायतें और लिपिक की कार्यप्रणाली निरीक्षण नोट में दर्ज कर ली गई।

कानूनी कार्रवाई की तैयारी :

डीसीओ खुशीराम भार्गव ने बताया कि रिपोर्ट सहायक चीनी आयुक्त, बरेली को भेज दी गई है। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जा रहा है। किसानों के शोषण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। निरीक्षण में बाबूराम, उद्देश्य कुमार व कंचन लाल समेत किसान उपस्थित रहे, जिन्होंने विभाग का समर्थन किया। विभाग की सक्रियता से अन्य केंद्रों पर हड़कंप मच गया है।

उत्कृष्ट कार्य से लोकतंत्र को मजबूती, डीएम ने 49 बीएलओ को किया सम्मानित

शतप्रतिशत मैपिंग कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ को मिला सम्मान जिलाधिकारी ने बीएलओ से किया संवाद

(जीएनएस)।

बाराबंकी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियानझ2026 के अंतर्गत जनपद में मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन निरंतर प्रभावी पहल कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने शतप्रतिशत मैपिंग कार्य करने वाले 49 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। इन बीएलओ ने अपने-अपने क्षेत्रों में 100 प्रतिशत मैपिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर अभियान को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि टीम वर्क और समर्पण का उदाहरण भी है।

सहयोग और प्रेरणा से मिलेगा लक्ष्य

डीएम ने बीएलओ से आ'ान किया कि वे जिस निष्ठा, जिम्मेदारी और दक्षता के साथ कार्य कर रहे हैं, उसी भावना से आगे भी कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है।

बीएलओ से विशेष संवाद, सुझावों का आदानझप्रदान

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सभी सम्मानित बीएलओ के साथ विशेष संवाद भी किया। इस संवाद में बीएलओ ने फील्ड स्तर पर आ रही व्यवहारिक चुनौतियों, मतदाता जागरूकता बढ़ाने के अनुभवों तथा कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े अपने सुझाव साझा किए। जिलाधिकारी ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और उन्हें आगामी कार्ययोजना में शामिल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्यरत बीएलओ के सुझाव अभियान को और अधिक मजबूत, सरल एवं प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। जिलाधिकारी ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयास, आपसी समन्वय और निरंतर परिश्रम से जनपद न केवल निर्धारित लक्ष्य हासिल करेगा, बल्कि उत्कृष्टता की नई मिसाल भी कायम करेगा।

आईएएस नंदनी चक्रवर्ती कौन हैं? पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनकर रचा इतिहास

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इससे पहले राज्य में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी फेरबदल हुई हैं। राज्य के मुख्य सचिव के पद पर आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती की नियुक्ति की गई है। वह राज्य में ये सर्वोच्च प्रशासनिक पद संभालने वाली पहली महिला और पहली बंगाली महिला अधिकारी हैं।

नंदिनी चक्रवर्ती ने मनोज पंत (आईएएसः 1991 बैच) का स्थान लिया, जो बुधवार को छह महीने के सेवा विस्तार के बाद सेवानिवृत्त हुए। पंत को जून 2025 में सेवानिवृत्त होना था पर वह 31 दिसंबर, 2025 तक पद पर रहे। उन्होंने सितंबर 2024 में भगवती प्रसाद गोपालिका (आईएएसः 1989 बैच) की सेवानिवृत्ति के बाद यह पदभार संभाला था।

बुधवार को इस घोषणा के साथ निवर्तमान मुख्य सचिव मनोज पंत के उत्तराधिकारी पर लगी अटकलों पर विराम लग गया। मनोज पंत का बुधवार को मुख्य सचिव के रूप में अंतिम दिन था। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले पंत को 31 दिसंबर तक छह महीने का सेवा विस्तार मिला। इस फेरबदल के बाद, उन्हें अब मुख्य सचिव के समकक्ष मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया।

कौन हैं कअर नंदिनी चक्रवर्ती?

1994 बैच की आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती ऐसे महत्वपूर्ण समय में कार्यभार संभाल रही हैं, जब राज्य 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है। उनकी नियुक्ति से पहले, वह गृह सचिव के पद पर कार्यरत थीं। नंदिनी चक्रवर्ती के स्थान पर 2004 बैच के आईएएस अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा को गृह विभाग में सचिव-स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई।

प्रमुख पद और जिम्मेदारियां

अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने कई अहम पद संभाले हैं

अपर मुख्य सचिव, गृह एवं हिल्स (पर्वतीय) कार्य विभाग

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की

प्रधान सचिव

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पश्चिम बंगाल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम

प्रबंध निदेशक, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम

जिलाधिकारी, हावड़ा

उद्योग, सूचना एवं संस्कृति, सुंदरबन कार्य, पर्यटन और जैव प्रौद्योगिकी विभागों में वरिष्ठ पद

इन सभी क्षेत्रों में काम करने के कारण वे राज्य की सबसे प्रभावशाली प्रशासनिक अधिकारियों में गिनी जाती हैं।

राजभवन कार्यकाल और प्रशासनिक विवाद

राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के साथ प्रधान सचिव के रूप में कार्य करते समय नंदिनी चक्रवर्ती काफी चर्चा में रहीं। इस दौरान राजभवन और राज्य सरकार के बीच असामान्य प्रशासनिक मतभेद सामने आए।

राज्यपाल कार्यालय ने उन्हें पद से मुक्त करने का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य सरकार ने पहले उन्हें उसी पद पर बने रहने का निर्देश दिया। मामला बढ़ने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया और राज्यपाल से अलग-अलग बातचीत की।

इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें राजभवन से हटाकर पहले पर्यटन विभाग की सचिव नियुक्त किया और बाद में दिसंबर 2023 में गृह एवं हिल्स कार्य विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी।